डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जनवरी, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 जनवरी, 2023

| वर्ष 66 | अंक 15 | भोपाल | 1 जनवरी, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को पूर्व सरकार द्वारा बंद की गई सुविधाएँ फिर से मिलेंगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

1071 लघु वनोपज समिति प्रबंधकों का बढ़ाया जाएगा मानदेय   मध्यप्रदेश के वन बनेंगे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के वनवासी भाइयों को वनों के उत्पाद से अधिकाधिक लाभ दिलवाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस कड़ी में वन मेला भी वनोपज उत्पादकों की आय वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। वन्य-प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश विशेष पहचान बना रहा है। वनों से वनवासियों को आर्थिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से भी फैसले लिए गए हैं।

मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक आए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" है। वन मेले का आयोजन वन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वनोपज से स्थानीय वनवासियों को लाभ दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से तेंदूपत्ता संग्राहकों को हानि नहीं होती। पेसा एक्ट में वनवासी क्षेत्र की पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य पेसा विकासखण्डों में पंचायतों के माध्यम से हो सकेगा। वर्ष 2017 और 2018 में तेंदूपत्ता श्रमिकों को पानी की कुप्पी, साड़ी और चप्पल आदि सामग्री प्रदाय की गई थी। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को ये सुविधाएँ देना बंद कर दी। इसके बाद कोरोना काल में व्यवस्थाएँ प्रभावित हुई। राज्य सरकार इस वर्ष से 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को यह सामग्री फिर से प्रदान करेगी। जनजातीय बंधु और अन्य वनवासी बंधुओं का हित सुनिश्चित किया जाएगा। चिरौंजी का समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, जिससे वनवासियों को पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनवासी क्षेत्र के लोगों के हित में निरंतर कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इनका मानदेय वर्ष 2016 में 5 हजार रूपए था, जो 6 हजार रूपए किया गया था। इसे बढ़ा कर 10 हजार रूपए तक लाने का कार्य हुआ। अब इसमें पुन: वृद्धि कर 13 हजार रूपए मासिक किया जाएगा। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

श्री पोरवाल सहकारिता सचिव बने

भोपाल : भोपाल राज्य शासन ने आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। आदेश के मुताबिक प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के. सी. गुप्ता को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल प्रबंध संचालक म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर को सचिव सहकारिता पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत श्री रघुराज एम.आर.को प्रबंध संचालक पावर मैंनेजमेंट कंपनी लि. जबलपुर एवं पदेन सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही मार्कफेड के एम.डी. श्री अलोक कुमार सिंह को पंजीयक एवं आयुक्त सहकारिता तथा प्रबंध संचालक तिलहन संघ का प्रभार भी सौंपा गया हैं।

मध्यप्रदेश पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य

सहकारिता विभाग ने लोक सेवा गारंटी में 8 नई सेवाओं को जोड़ा ● परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के सुझावों पर अमल सुनिश्चित करें-मंत्री डॉ. भदौरिया

भोपाल : विभागीय परामर्शदात्री समिति में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल सुनिश्चित किया जाये। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस आशय के निर्देश दिये। समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, श्री शिवनारायण सिंह और श्री शिवदयाल बागरी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। पैक्स के माध्यम से 16 हजार 452 उचित मूल्य दुकानों का संचालनकिया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीजन के 14 लाख कृषक को 16 हजार 860 करोड़ रूपये के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 में साथ ही खरीफ सीजन के 19 लाख कृषक और रबी सीजन में अब तक 7 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। अब तक 14 हजार 699 करोड़ रूपये का फसल ऋण वितरण किया गया है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कटनी के नवाचार को देश की राजधानी में मिली सराहना

ज़िले के अमृत पुष्पक की उड़ान दिल्ली तक ● राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस सप्ताह के शुभारंभ समारोह में छाया रहा ज़िला प्रशासन का नवाचार

भोपाल : केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए "पाँच दिन का प्रशासन गाँव की ओर" राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरूआत की। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार ने संपूर्ण देश में किए गए उत्कृष्ट नवाचारों एवं प्रशासन के सार्थक प्रयासों की झलकियाँ प्रदर्शित करते हुए ज़िला प्रशासन एवं ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार "अमृत पुष्पक" को सराहा गया। विगत दिवस ज़िले के भ्रमण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी ज़िला प्रशासन के उक्त पहल की सराहना की गई थी।ज़िले में कृषि क्षेत्र में उन्नत ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने एवं कृषकों को ड्रोन तकनीक के प्रयोग के अपेक्षित लाभ से जागरूक करने के लिए कटनी ज़िला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा "अमृत पुष्पक" प्रोजेक्ट में स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम तेवरी में स्वीटकॉर्न की फसल पर ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव कर संपूर्ण देश में अग्रणी बना। इस प्रोजेक्ट ने देश में कृषि के क्षेत्र में ड्रोन क्रांति लाने एवं कृषि को इस तकनीक से जोड़ने में सेतु की तरह कार्य किया। इसी का परिणाम है कि किसानों को उन्नत खेती करने एवं ड्रोन तकनीक को रोज़गार के रूप में प्रयोग में लाने की प्रेरणा मिली। कटनी जिले के इस नवाचार की सफलता को देखते हुए मध्यप्रदेश के साथ अन्य प्रदेश भी अब फसल पर छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

कटनी जिला कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर "अमृत पुष्पक" नवाचार की सराहना इस ज़िले के लिए गर्व का विषय है। जिला कटनी प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस जिले में ड्रोन तकनीक के प्रचार-प्रसार के लिये लगातार प्रयासरत है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। विगत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिल के भ्रमण के दौरान जिले में हुए इस नवाचार की सराहना की गई थी।

जिला प्रबंधक ई-गवर्नेन्स सौरभ नामदेव ने बताया कि ड्रोन नई उभरती तकनीक है, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। इससे निकट भविष्य में इस क्षेत्र में अनेक रोज़गार की संभावनाएँ हैं। आमजन के प्रति इस उन्नत तकनीक को लेकर जागरूकता बढ़े इसी मंशा से ज़िले में "अमृत पुष्पक" का नवाचार किया गया। इस क्षेत्र में युवा अपना कैरियर बना सकें इस उद्देश्य से जन-जागरूकता के साथ ही प्रशिक्षण मुहैया कराये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कटनी में राज्य-स्तरीय ट्रेड फ़ेयर में भी प्रदर्शनी लगाकर नागरिकों और युवाओं को ड्रोन तकनीक की जानकारी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि "अमृत पुष्पक" प्रोजेक्ट में फसलों पर छिड़काव के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन का उपयोग किया गया। यह एक एकड़ की फसल के रकबे में महज 10 मिनट में रसायन के स्प्रे का कार्य पूरा कर सकता है। ड्रोन नैनो पार्टिकल्स का छिड़काव करता है जो परम्परागत छिड़काव पद्धति से कई गुना अधिक है। इससे तरल उर्वरक की खपत भी कम होती है। साथ ही पौधे की पत्तियों द्वारा पूरा अवशोषण भी होता है।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में "लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता" विषय पर हुई कार्यशाला

उत्तराखंड के वन मंत्री हुए शामिल

भोपाल : उत्तराखण्ड के वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जंगल लोगों की आजीविका से जोड़ने और जंगल को बचाने के लिए वर्तमान में बड़ा यक्ष प्रश्न है। वन मंत्री श्री उनियाल अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में 'लघु वनोपज से आत्म-निर्भरता' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे।

श्री उनियाल ने कहा कि जंगल का निर्माण आपसी सहयोग से संभव हुआ है, इसीलिए हमें जंगल बचाने में समुदाय सहभागिता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कान्फ्रेंस में विभिन्न आयुर्वेदिक और वन-शिक्षण संस्थाओं से शामिल हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुनिया का कोई लक्ष्य आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता।

राज्य लघु वनोपज संघ के एमडी श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि दो दिन तक चलने वाली कार्यशाला में देश-विदेश में हुए विभिन्न अनुसंधानों की जानकारी मिलेगी, जो आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता ने बताया कि वन मेले में लगे स्टालों से प्रदेश की जैव विविधता झलकती है। यहाँ एक ओर पातालकोट का विश्व विख्यात शहद, झाबुआ का लाल चावल, महाकौशल क्षेत्र का कोदो-कुटकी और कई तरह के पारम्परिक औषधीय पौधों की प्रचुरता है।

कार्यशाला में नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान के विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश सहित उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विषय-विशेषज्ञ, अधिकारी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट शामिल हुए।

नेपाल सरकार के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण सलाहकार डॉ. माधव कर्की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने मध्यप्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य के संसाधनों के सतत प्रबंधन और संवर्धन की तारीफ करते हुए कहा कि नेपाल को इस संदर्भ में सीखना होगा।

उत्तराखण्ड के वन मंत्री ने किया स्टाल का अवलोकन

वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने वन मेले में लगी विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त की। वन बल प्रमुख श्री आर.के. गुप्ता ने वन मंत्री को प्रतीक-चिन्ह भेंट किया।

इस मौके पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम भोपाल) के डायरेक्टर डॉ. के. रविचंद्रन की मौजूदगी विशेष रही। अपर प्रबंध संचालक (व्यापार) श्री विभाष ठाकुर ने आभार माना।

महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी करेगी "मुक्ता ब्रॉण्ड घी लाँच

बुंदेलखण्ड की 18 हजार से अधिक महिलाओं का है यह एफपीओ

भोपाल : बुंदेलखण्ड की 18 हजार 500 से अधिक महिला डेयरी किसान अपनी मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी के प्रोडक्ट "मुक्ता" ब्रॉण्ड घी को 16 दिसम्बर को विधिवत लाँच करेंगे। कार्यक्रम होटल पलाश में दोपहर 12 बजे से रखा गया है। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के सीईओ श्री एल.एम. बेलवाल, मुक्ता कम्पनी की अध्यक्ष श्रीमती रजनी रजक और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश में 4 लाख 12 हजार स्व-सहायता समूह गठित हैं, जिनसे 46 लाख ग्रामीण महिलाओं को जोड़ कर उनका आजीविका संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में 88 किसान उत्पादक कम्पनियाँ भी बनाई गई हैं, जिनके एक लाख 79 हजार सदस्य प्रमुख रूप से कृषि आधारित गतिविधियाँ कर रहे हैं। इन कम्पनियों का वर्ष 2022-23 में नवम्बर माह तक टर्न ओवर 529 करोड़ रूपये हो चुका है। गत वर्ष अकेली मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी ने 65 करोड़ रूपये से अधिक का कारोबार किया, जिसमें 85 प्रतिशत बिक्री से आय का भुगतान सदस्यों को दूध के रूप में किया गया। मुक्ता कम्पनी ने इण्डिया डेयरी अवार्ड-2021 में डेयरी एक्सटेंशन पुरस्कार प्राप्त किया।

सिंचाई परियोजनाओं को तय समय- सीमा में पूरा करें : मुख्यमंत्री

748 करोड़ 57 लाख रूपए लागत की 6 वृहद सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत

परियोजनाओं के पूरा होने से 38 हजार 470 हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकेगी सिंचाई

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के लिए निर्मित होने वाली वृहद परियोजनाओं का कार्य तय समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल संसाधन विभाग की 6 वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति की अनुशंसा की। इन परियोजनाओं के पूरा होने से 38 हजार 470 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित लागत 748 करोड़ 57 लाख रूपए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 117 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना

बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में बड़ी उतावली नदी पर प्रस्तावित पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 112 करोड़ 50 लाख रूपये है। परियोजना के पूरा होने से बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 10 ग्रामों में 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

हरबाखेड़ी बैराज मध्यम परियोजना

उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित हरबाखेड़ी बैराज मध्यम परियोजना स्वीकृत की गई। यह परियोजना माइक्रो सिंचाई पद्धति पर आधारित है। परियोजना की अनुमानित लागत 104 करोड़ 28 लाख रूपए है। परियोजना में 10.76 एम.सी.एम. के बैराज तथा दाब युक्त पाइप नहर निर्माण का कार्य शामिल है। परियोजना के पूरा होने से महिदपुर तहसील में 3050 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई हो सकेगी।

लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना

बालाघाट जिले के परसबाड़ा विकासखण्ड में प्रस्तावित लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना को स्वीकृति दी गई। परियोजना में लगभग 100 वर्ष पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त हिस्से की अपस्ट्रीम में पम्प हाउस का निर्माण कर हॉज सिस्टम से 55 ग्रामों की 9,630 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ (धान) की फसल में सिंचाई की जा सकेगी। परियोजना की लागत 137 करोड़ 26 लाख रूपये है।

जैरा मध्यम माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना

सागर जिले की जैरा मध्यम माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसकी अनुमानित लागत 102 करोड़ 52 लाख रूपये है। इससे 5400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें बाँध निर्माण, प्रेशराइज्ड पाईप इरिगेशन प्रणाली का कार्य किया जाएगा।

सामाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना

उज्जैन जिले की सामाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसकी अनुमानित लागत 141 करोड़ 11 लाख रूपये है। इससे लगभग 6 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसके अंतर्गत बैराज निर्माण, प्रेशराइज्ड पाईप इरिगेशन प्रणाली विकास कार्य शामिल हैं।

टेम मध्यम् सिंचाई परियोजना

विदिशा जिले की टेम मध्यम् सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में बाँध निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। परियोजना में बाँध निर्माण तथा प्रेशराइज्ड पाइप नहर निर्माण का कार्य शामिल है। परियोजना की अनुमानित लागत 151 करोड़ 28 लाख रूपये है। परियोजना से भोपाल जिले की बेरसिया तहसील एवं गुना जिले की मकसूदनगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 9,990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पोषक अनाज : वैश्विक परिदृश्य

मोटे अनाजों का मानव जाति के भोजन में भागीदारी ईसा पूर्व 3000 से मिलती है। मोटे अनाज विश्व के 131 देशों में उगाए जाते हैं, वहीं एशिया और अफ्रीका के 59 करोड़ लोगों का यह पारंपरिक भोजन है। मोटे अनाजों के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत ही है, परंतु एशिया का 80 प्रतिशत मोटा अनाज भारत में ही होता है। एशिया और अफ्रीका बाजरे के प्रमुख उत्पादक और खपत वाले देश हैं। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार 112 देशों में और प्रोसो बाजरा (सामान्य बाजरा) विश्व के 35 देशों में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। ज्वार और पर्ल बाजरा 90 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन को कवर करते हैं। भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा के साथ कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष

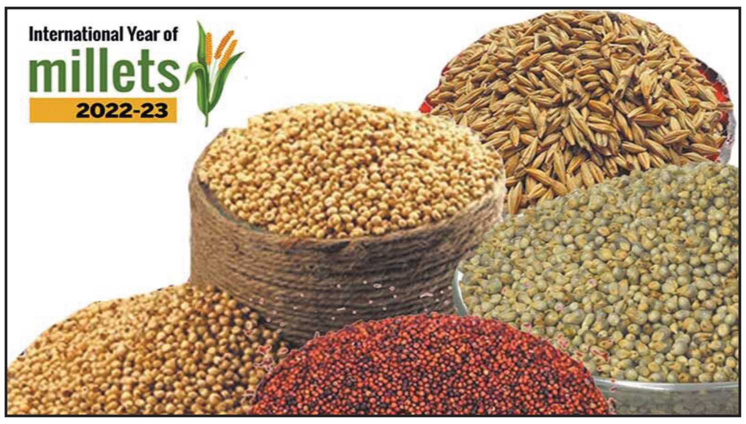

(आईवायओएम) घोषित किया गया है और भारत इसका नेतृत्व करेगा। बली से लेकर खली तक सभी बाजरा के मुरीद हैं।

भारत में मोटे अनाज की स्थिति

देश में पोषक अनाज का उत्पादन 2019-20 के दौरान 17.26 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2020-21 में 18.02 मिलियन टन हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज मिशन को 14 राज्यों के 212 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएफएसएम के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को मोटे अनाज की खेती की उन्नत पद्धतियों पर क्लस्टर प्रदर्शन, एचआईवी/संकर किस्मों के बीजों का वितरण, उन्नत फार्म मशीनरी, पोषक तत्व प्रबंधन, फसलोपरांत कटाई उपकरण एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए मदद की जाती है।

मोटे अनाज अब पोषक अनाज के रूप में जाने जाते हैं। मोटे अनाज यानी ज्वार, बाजरा, रागी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 4 वर्ष पहले 2018 में मोटे अनाज (मिलेट) को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया है।

सुगम आवाजाही

पोषक अनाज की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने पोषक अनाज के उत्पादन को अन्य राज्यों में आवाजाही के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन भी किया है।

सरकारी स्कूलों में

सरकार वर्ष 2025-26 तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की पीएम पोषण योजना के तहत मोटे पोषक अनाज के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों को पोषक अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के नजरिए से सरकार हर साल तीन प्रमुख पोषक अनाज यानी ज्वार, बाजरा, रागी के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी कर रही है। हाईब्रिड ज्वार की एमएसपी वर्ष 2017 में 1700 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो वर्ष 2022 में 2970 रूपए प्रति क्विंटल है, वहीं बाजरा 1425 रुपए प्रति क्विंटल 2017 में था, सरकार ने वर्ष 2022 में इसकी एमएसपी 2350 रुपए प्रति क्विंटल की है। इसी प्रकार रागी भी वर्ष 2017 के 1900 रुपए से बढ़कर 2022 में 3578 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है।

हरित क्रांति के पूर्व

कृषि में हरित क्रांति का दौर आया और हम गेहूँ, चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए और निर्यात भी भरपूर करते हैं, परंतु गेहूँ-चावल की दौड़ में ज्वार, बाजरा पिछड़ गए। वर्ष 1965-70 तक भारत के खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी, जो आज घटकर केवल 6 प्रतिशत रह गई। हरित क्रांति के दौर वर्ष 1965-70 के बाद मोटे अनाजों का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर कम हुआ।

बाजार की औसत उत्पादकता

विश्व : 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

भारत : 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

शीतलहर-पाले से फसल सुरक्षा के उपाय

भोपाल। पाला रबी के मौसम में किसानों की एक प्रमुख समस्या होती है। इस ऋतु में तापमान कम होने के साथ-साथ जैसे ही ठंड बढ़ती है और तापमान कम होते- होते जमाव बिन्दु तक आ जाता है तो वातावरण में पाले की स्थिति बनने लगती है, इसे कोहरा भी कहा जाता है। इसके कारण प्रतिवर्ष रबी में फसल उत्पादकता के साथ-साथ सब्जी उत्पादक को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसके प्रभाव से फसलों एवं सब्जियों के फूल मुरझा जाते है और झडने लगते हैं। इसके कारण उनमे दाने नहीं बन पाते एवं चपटे होकर काले पड़ जाते हैं। प्रभावित फसल का हरा रंग समाप्त हो जाता है तथा पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसा दिखने लगता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सडने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों एवं अन्य कीटों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। पत्ती, फूल एवं फल सूख जाते हैं। फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं व स्वाद भी खराब हो जाता है। फलदार पौधे पपीता, आम आदि में इसका प्रभाव अधिक पाया गया है।

पाले से बचाव एवं सुरक्षा के लिए पाले का पूर्वानुमान लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है। प्राय: पाला पडने की संभावना उस रात में ज्यादा रहती है जब ये स्थितियां बनती हैं-

- जब दिन के समय ठंड अत्यधिक हो परंतु आकाश साफ हो।
- भूमि के निकट का तापमान शून्य डिग्री सेंटीग्रेड अथवा और कम हो।
- शाम के समय हवा अचानक रुक जाए एवं हवा में नमी की अत्यधिक कमी हो।

सुरक्षा के उपाय

खेत की सिंचाई की जाए – यदि पाला पडने की संभावना हो या मानसून विभाग से पाला पडने की चेतावनी दी गई हो तो फसलों की हल्की सिंचाई करें जिससे खेत के तापमान में 0.5 से 2 डिग्री से.ग्रे. तक वृद्धि हो जाएगी इससे फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

पौधों को ढकें – पाले से सर्वाधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को प्लास्टिक की चादर, पुआल आदि से ढंक दें ऐसा करने से प्लास्टिक के अन्दर का तापमान 2-3 डिग्री से. ग्रे. तक बढ़ जाता है जिससे तापमान जमाव बिन्दु तक नहीं पहुंच पाता और पौधा पाले से बच जाता है। पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे का दक्षिण-पूर्वी भाग खुला रहे ताकि उन्हे सुबह और दोपहर को धूप मिलती रहे।

खेत के पास धुआँ करना- फसल को पाले से बचाने के लिए खेत के किनारे धुआँ करने से तापमान में वृद्धि होती है जिससे पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है।

रस्सी द्वारा – पाले के समय रस्सी का उपयोग करना काफी प्रभावी रहता है, इसके लिए दो व्यक्ति सुबह के समय (भोर में) एक रस्सी को उसके दोनों सिरों में पकडक़र खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक फसल को हिलाते हैं, जिससे फसल पर पड़ी हुई ओस नीचे गिर जाती है और फसल सुरक्षित हो जाती है।

पाले से बचाव के दीर्घकालीन उपाय

फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत के उत्तर-पश्चिम मेड़ पर तथा बीच-बीच में उचित स्थान पर वायु रोधक पेड़ जैसे- शीशम, बबूल, खेजड़ी, आड़ू, शहतूत, आम तथा जामुन आदि के लगाए जाएं तो सर्दियों में पाले व ठण्डी हवा के झोकों के साथ ही गर्मी में लू से भी बचाव हो सकता है।

गुनगुने पानी का छिडक़ाव- प्रात: काल फसल पर हल्के गुनगुने पानी का छिडक़ाव हो सकता है, छोटी नर्सरी या बगीचे में इस तकनीक का उपयोग सरलता से किया जा सकता है।

वायुरोधी टाटिया का उपयोग- नर्सरी में तैयार हो रहे पौधों को पाले से ज्यादा नुकसान होता है अत: वायुरोधी टाटिया को नर्सरी में हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधकर क्यारियों के किनारों पर लगाएं तथा दिन में हटा दें।

अत: देखा जा सकता है कि पाले के कारण रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। किसान बंधु ऊपर वर्णित किसी भी विधि का उपयोग अपनी सुविधा अनुसार कर पाले से फसल का बचाव कर सकता है।

सरसों को पाले से बचाएं

जिस तरह से फसलों को उगाने में परिवर्तन आया है और सरसों की फसल ने क्षेत्रफल की दृष्टि से उग्रता हासिल की है, उसके विपरीत सरसों ही पाला से अधिक प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी का एक कारण बन जाती है।

सरसों की फसल में पाले का असर तने से ज्यादा जड़ों और पत्तियों पर एवं पत्तियों से ज्यादा फूलों पर पड़ता है। फूलों में विशेष रूप से अंडाशय की अधिक हानि होती है। पाले से पत्तियां और फूल झुलस/मुरझा जाते हैं। झुलसकर बदरंग हो जाते हैं। दाने काले पड़ जाते हैं तथा फलियों में हरे दाने पानी में परिवर्तित हो जाते हैं।

सरसों की फसल को अधिकतर किसान भाई बहुत ही जल्दी सितम्बर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बो देते हैं जिसकी वजह से दिसम्बर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचता है तो उधर फसल पर फूल और फलियों का लदान अधिकतम होता है। फलस्वरूप फसल पाले से नुकसान उठा जाती है। अत: सरसों की बुआई अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक अवश्य कर दें जिससे पाले से बचा जा सके।

पाले से बचाव के उपाय

- यदि पाला पडने की संभावना का पता चल जाय तो सरसों के खेत में हल्की सिंचाई करें।
- जिस रात्रि में पाला पडने की संभावना हो उस समय खेत की पश्चिमी मेड़ों पर करीब आधी रात को कुछ घांस-फूस इकट्ठा करके जलायें, जिससे धुआं सारे खेत में छा जाये। इससे भूमि की गर्मी कम निकलती है और आसपास में तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार धुआं कई स्थानों पर करें और उसका रुख फसल पर होकर जाना चाहिये।
- सरसों की फसल में पाला पडने के पहले 2 प्रतिशत यूरिया का छिडक़ाव किया जाय तो, पाले का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि यूरिया के छिडक़ाव से कोशिकाओं में पानी आने-जाने की क्षमता बढ़ जाती है।
- सरसों की आर.एच. 30 किस्म पर पाले का असर कम होता है और पैदावार भी अच्छी होती है।

वर्तमान स्थिति में गाजर और टमाटर फसल का रखरखाव कैसे करें

भोपाल: गाजर-टमाटर सब्जी फसल के रखरखाव के सम्बंध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. आर.के. यादव सब्जी विज्ञान संभाग ने बताया कि वर्तमान में 40 से 45 दिन की गाजर फसल हो गई है। बीज की अधिकता के कारण खेत में जहाँ पौधे अधिक एवं घने हो गए हो वहाँ पतली जड़ वाले पौधों को निकाल दें जिससे पौधों की सघनता कम हो जाएगी और पौधों को पर्याप्त मात्रा में हवा-पानी मिलेगा। इसके पश्चात नत्रजन की मात्रा डालें तथा मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गाजर की नेमटीस और पूसा नयनज्योति किस्में किसानों द्वारा लगाई जा रही है।

डॉ. यादव ने बताया कि टमाटर में अर्लीब्लाईट रोग होता है जिसमें पौधे की पत्तियों में छल्ले बन जाते है। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन एम-45, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि टमाटर पौधे के पत्तों में लेट ब्लाईट रोग आता है, जिसमें धब्बे बन जाते है। इसकी रोकथाम के लिए रिडोमिल दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना उचित होता है।

पूसा के वैज्ञानिकों ने म.प्र. के किसानों की समस्याओं का समाधान किया

पपीते में मिली बग

पपीता में मिलीबग की रोकथाम के लिए कार्बोसल्फान की 300 एम.एल. की मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।

गेहूं की जड़ों में दीमक

गेहूँ की जड़ों में दीमक एवं गलन का प्रकोप की रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफॉस 3 लीटर मात्रा 50 किलोग्राम मिट्टी में 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर हल्की सिंचाई करें।

टमाटर

टमाटर में टोमैटो लीफ कर्ल रोग से बचाव के लिए रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटाएं तथा इमिडाक्लोप्रिड की 80 एम.एल. मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।

लहसुन

लहसुन की पत्तियाँ मुडऩे को माईट्स प्रकोप कहते हैं। इसका प्रकोप रोकने के लिए डाईकोफॉल की 500 एम.एल. मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करे।

पेसा अधिनियम से जनजातीय वर्ग की जिंदगी बदल जाएगी : श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने युवा परिसंवाद में युवाओं को संबोधित किया

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा अधिनियम को जमीन पर उतार कर जनजातीय वर्ग की जिंदगी बदलने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में जल, जंगल, जमीन के लिए लोगों को अधिकार देने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर प्रदेश में लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम लागू कर लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर युवा परिसंवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पेसा अधिनियम के विषय में सरलभाषा और विस्तार से युवाओं को जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के लिए युवाओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि गांव का पैसा गांव में रहे इसके लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। ग्राम सभा साल भर के कार्यों की योजना बनाएगी। ग्राम सभा ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी। अधिसूचित गांव में नई शराब और भांग की दुकान खोलने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भी ग्राम सभा प्रतिबंध लगा सकती है। गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे-मोटे झगड़ों, विवादों के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। पेसा अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं। पेसा अधिनियम सामाजिक क्रांति है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवा गांव-गांव जाएं और लोगों को पेसा अधिनियम के बारे में समझाएं। मुझे इसके लिए आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। मामा आपके साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में गंभीरतापूर्वक सहयोग करें। सामाजिक क्रांति लाकर हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। कार्यक्रम में डॉ निशांत खरे सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवा उपस्थित थे।

ककून मार्केट में रेशम कोया बिक्री से कृषकों को दुगुनी आमदनी

भोपाल। रेशम उत्पादन एक ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग है जो कि विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है। इससे बहुत ही अधिक मांग में रहा प्राकृतिक रेशम जो कि वस्त्रों की रानी भी कहलाता है। यह ग्रामीण कृषकों के लिए उत्तम है और निर्धनों को पर्याप्त आय व रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जिससे कम समय में अधिक रोजगार और आकर्षक आय प्राप्त होती है। भारत लगभग 35,000 मी. टन वार्षिक उत्पादन करने के साथ दुनिया में द्वितीय स्थान पर है और रेशम का बड़ा उपभोक्ता भी है। रेशम का उत्पादन जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में परम्परागत रूप से हो रहा है। यह उद्योग दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं राज्य रेशम विभाग के सुदृढ़ सहयोग से तथा कृषकों के अथक प्रयासों से भी देश के उत्तरी मध्य राज्यों में खासकर मध्यप्रदेश में विगत 20 वर्षों से कृषकों द्वारा रेशम कार्य अपनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य की विशेषता यह है कि भारत देश में पाया जाने वाला चारों प्रकार का वाणिज्यिकी फसल जैसे शहतूत, एरी, मूगा एवं तसर की पैदावार होशंगाबाद जिले में होती है।

बाजार की समस्या दूर हुई

मध्यप्रदेश के रेशम उत्पादक कृषकों के सामने मुख्य समस्या उचित कोया विक्रय बाजार की रही है। विगत वर्षों में मध्यप्रदेश सिल्क फैडरेशन द्वारा कोया खरीद चार्ट के अनुसार अनुमोदित (कोया की गुणवत्ता के आधार पर) द्विप्रज संकर रेशम कोया की अधिकतम दर प्रति किलोग्राम रूपये 350 एवं न्यूनतम दर रूपये 130 की दर से एवं बहुफसलीय कोया की दर रूपये 220/- व रूपये 90/- की दर पर खरीद की जा रही थी। अनुसंधान प्रसार केन्द्र, होशंगाबाद के अध्ययन के आधार पर एक किलोग्राम रेशम कोया उत्पादन के लिये न्यूनतम रूपये 220/- से रूपये 250/- तक की लागत खर्च का आकलन किया गया है। क्योंकि रेशम कृषकों ने विक्रय दर कम होने पर अपेक्षा अनुरूप आय/लाभ प्राप्त नहीं होने से समय-समय पर असंतोष प्रकट किया था। इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के रेशम विभाग ने संज्ञान में लेते हुए रेशम कृषकों के हित में शासकीय ककून मार्केट, जिला रेशम कार्यालय परिसर मालाखेड़ी, नर्मदापुरम में व्यवस्थित रेशम कोया क्रय-विक्रय मार्केट की व्यवस्था को वर्तमान में चालू की गई है। उक्त ककून मार्केट में सरकार की ओर सभी सुविधायें के साथ रेशम उत्पादक कृषक एवं मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के डीलर्स/ व्यापारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर रेशम कोया की खरीद की जा रही हैं। विगत माह में खुले बाजार में द्विप्रज संकर रेशम कोया का औसत दर प्रति किलोग्राम लगभग रूपये 500 की दर से व्यापारियों द्वारा खरीद की गई है। कोया बाजार में रेशम उत्पादक कृषक अपना उत्पादित रेशम कोया को उचित दर पर विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। रेशम कृषकों को दुगुना (डबल आय) लाभ मिलने से रेशम उत्पादक कृषकों में नई उमंग के साथ उत्साह का संचार हुआ है। इस व्यवस्था का खुले मन से रेशम कृषकों ने स्वागत कर प्रशंसा व्यक्त की है। आगे रेशम कृषक नये ढंग से रेशम की खेती करने में और अधिक रूचि दिखाएंगे। इस संबंध में पूर्व आयुक्त, श्री विशेष गढ़पाले, (आईएएस) ने संज्ञान में लेकर कोया मार्केट की व्यवस्था में अपना योगदान देकर मार्केट को सफलतापूर्वक संचालन कराने में अहम भूमिका का निर्वहन किया।

वैज्ञानिक-डी अनुसंधान प्रसार केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, होशंगाबाद ने समस्त रेशम कृषकों से आग्रह किया कि शहतूत बगीचे का उचित रखरखाव के साथ ही रेशम कीटपालन कार्य में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अधिक से अधिक मात्रा में गुणवत्तायुक्त रेशम कोया उत्पादन कर और अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषक दो एकड़ शहतूत बगीचे से हर माह 250 डीएफएल का कीटपालन कर लगभग 200 किलोग्राम कोया उत्पादित कर उक्त विक्रय दर से प्रति माह लगभग एक लाख रूपये की कमाई की जा सकती है जो कि शुद्ध लाभ प्रतिमाह लगभग रूपये 60,000 से 70,000 तक मिल सकता है।

आइसबॉक्स वाली बाइक बढ़ाएगी मछली की बिक्री

देवास: मत्स्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत जिले में मनरेगा अंतर्गत एक हैक्टेयर से तीन हैक्टेनयर के 32 अमृत सरोवर एवं 37 पुष्कर सरोवर कुल 69 तालाबो में समूह के माध्यतम से 05 लाख 91 हजार फिंगरलिंग मिश्रित बीज का संचयन किया गया। जिसमें 26-50 एमएम आकार की कतला, रोहू, नरेन और कामन कार्प प्रजाति के बीज हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत मोटर सायकल विथ आइसबॉक्स 13 हितग्राहियों को दी गई। जिसकी कुल राशि 05 लाख 85 हजार रूपये है। हितग्राहियों को मोटर सायकल विथ आइसबॉक्स देने से सुगमता से विक्रय कर सकते हैं। आइसबॉक्स होने से मछली भी खराब नहीं होगी।

बता दें कि जिले के 32 अमृत सरोवर एवं 37 पुष्कर सरोवर कुल में 69 तालाबों में सितम्बर माह में फिंगरलिंग मिश्रित बीज डाले गये थे, जो दिसम्बर माह में उन्नत मछली के रूप में तैयार हो गये हैं और मछली का स्थानीय बाजार में अच्छे मूल्य पर विक्रय हो रहा है। जिससे समूह के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मछली पालन आजीविका का साधन भी बन गया है। हितग्राहियों द्वारा आसपास की बड़ी मण्डियों में आने वाले समय में मछलियों को विक्रय किया जायेगा, जिससे समूह से जुड़े लोगों को और अधिक लाभ मिलेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिले में विकासखण्ड बागली, देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद और खातेगांव में सौ नये अमृत सरोवर तालाब बनाये जा रहे हैं। जिसमें 44 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण हो गया है। 56 अमृत सरोवरों का कार्य प्रगतिरत है। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर 186 पुष्कार तालाब बनाये जा रहे हैं, जिसमें 65 पुष्करर तालाबों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 121 पुष्करर तालाबों का कार्य प्रगतिरत है। विभाग द्वारा हितग्राहियों को मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्धी कराई जा रही है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को पूर्व सरकार...

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन मेले में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया और वन विभाग एवं मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ की टीम को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन मेला परिसर में विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और स्टाल संचालकों से उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में ईएमएफपी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया।

महुए की बढ़ती कीमत वनवासियों को दिलवाएगी लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का महुआ जो 20 या 30 रूपए किलो तक बिकता था, अब विदेशों तक पहुँच रहा है। डेढ़ सौ रूपए किलो तक इसके दाम बढ़ गए हैं। इंग्लैंड सहित कई देशों में महुआ से चाय बनाई जा रही है। इसके औषधीय गुण भी हैं। इसी तरह हर्रा, बहेड़ा और आँवला आदि उत्पाद गरीबों की आय बढ़ाने के माध्यम हैं। मुलेठी जैसी औषधियाँ दैनिक उपयोग में काम आ रही है। लोगों को निरोग रखने और वनवासी गरीब भाइयों की आय बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का विशेष महत्व है।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि जब से वन मेले का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप सामने आया है, इसका महत्व बढ़ गया है। इस स्वरूप में वन मेले का आज 9वां वर्ष है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा के अनुरूप वनों के उत्पाद के विक्रय से जुड़े लोगों की आय निरंतर बढ़ रही है। बायर-सेलर मीट से वनवासियों को लाभ हुआ है। महुआ संग्रहण का कार्य आधुनिक तकनीक से हो रहा है, जिससे महुआ की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिली है। इस वजह से महुआ के अच्छे दाम देश-विदेश में मिल रहे हैं। वन मेले में पूर्व में जो करारनामे हुए थे वे 14 करोड़ के थे। इस वर्ष 25 करोड़ रूपए तक के करारनामे होने की संभावना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान का पुष्प-गुच्छ और स्मृति-चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामकिशोर कांवरे और अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासक मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ श्री जे.एन. कंसोटिया सहित बड़ी संख्या में नागरिक और मेला प्रतिभागी उपस्थित रहे।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सहकारिता सशक्त माध्यम - श्री शर्मा

रतलाम। बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सहकारिता सशक्त माध्यम साबित हो सकता है। जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता वह काम साथ मिलकर किया जा सकता है। भारत में सहकारी बिजनेस मॉडल को सफल नहीं कहा जा सकता है, वहीं निजी में सारा धन एक ही हाथों में होता है तथा समाज के लिए भी वह लाभदायी नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में सहकारी बिजनेस मॉडल सफल हो सकता है तथा इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमूल के रूप में हमारे सामने है।

उक्त विचार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी संघ मर्यादित रतलाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिरुद्ध शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की क्षेत्रिय शिक्षा परियोजना जावरा द्वारा सी. एम. राईज महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जावरा में 'सहकारी बिजनेस मॉडल' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए।

श्री शर्मा ने कहा कि अमूल, इफको, कृभको, सांची जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने है जो सहकारी बिजनेस मॉडल पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था भी सहकारिता के अनुकूल है। सहकारिता के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के अलावा फूड प्रासेसिंग, जैविक उपज का विक्रय, श्रम ठेका, गणवेश, सिक्यूरिटी, महिला लघु उद्योग जैसी सहकारी संस्थाओं का गठन किया जा सकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्राचार्य राजेन्द्र बोस ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को सहकार से समृद्धि व स्वरोजगार विषय पर मार्गदर्शन दिया। विद्यालय के उप प्राचार्य संजय श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण एवं परियोजना का परिचय प्रजापालसिंह चन्द्रावत ने दिया तथा परियोजना के सहकारी शिक्षा अनुदेशक पंकज दीक्षित द्वारा भी सहकारी बिजनेस मॉडल विषय पर विद्यार्थियों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मार्गदर्शित किया गया। कार्यक्रम में जिला सहकारी संघ के जनसम्पर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट, वरिष्ठ व्याख्याताद्वय सुनील भट्ट, अपारसिंह गंभीर भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन सहकारी शिक्षा अनुदेशक गिरिराजसिंह राठौर ने किया तथा आभार प्रदर्शन कार्यक्रम की संयोजक एवं परियोजना की महिला प्रेरक राजलक्ष्मी चन्द्रावत द्वारा किया गया

श्री शाजी ने नाबार्ड चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया

मुंबई। श्री शाजी केवी ने गत 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, वे 21 मई, 2020 से नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे और सॉफ्टवेयर आधारित पर्यवेक्षी निरीक्षण, डेटा-वेयरहाउस, प्रक्रिया पुन: जैसी पहलों को लागू करने के अलावा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने की महत्वाकांक्षी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नाबार्ड में शामिल होने से पहले, उन्होंने केनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया। उन्हें केरल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष होने के अलावा विभिन्न संगठनों जैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. और केनरा बैंक सिक्योरिटीज लि. में लगभग 10 वर्षों का व्यापक बोर्ड स्तर का अनुभव प्राप्त है।

श्री शाजी कृषि में स्नातकोत्तर हैं और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा के अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से सार्वजनिक नीति में पीजीडीएम रखते हैं। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित सहयोगी और एनएसई प्रमाणित मार्केट प्रोफेशनल(एनसीएमपी) भी हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मध्यप्रदेश पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य....

पीएम किसान योजना के सहकारी बैंकों के पात्र हितग्राहियों को 39 लाख 57 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

बताया गया कि विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ, धान और अन्य फसलों का उपार्जन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राज्य सहकारी आवास संघ, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक में बैंकिंग सेवाओं संबंधी जानकारी भी दी गई।

सहकारिता के विकास में महिलाओं की भागीदारी

जबलपुर. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित शालेय निबंध प्रतियोगिता के घोषित परिणाम के अनुसार गत दिवस पुरस्कार वितरित कर दिए गए. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमरहाई जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित करते हुए शाला की प्राचार्य श्रीमती मिथिलेश चौधरी ने कहा कि निबंध प्रतियोगिता से छात्राओं को सहकारिता का अर्थ और उसके विकास में महिलाओं के योगदान को समझने में मदद मिलेगी.

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने इस अवसर पर प्रतियोगिता के विषय सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला. केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे ने राज्य सहकारी संघ और सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों के विषय में जानकारी देते हुए महिलाओं की सहकारी समितियों के संबंध में समझाइश दी.

कार्यक्रम का संचालन शाला की शिक्षिका श्रीमती कीर्ति परौहा और केन्द्र के कंप्यूटर प्रशिक्षक श्री शोभित ब्यौयहार ने किया. आभार प्रदर्शन श्री एन, पी. दुबे ने किया. निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं के अतिरिक्त सभी प्रतिभागी छात्राओं को भी प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किये गए. केन्द्र की ओर से मनमोहक गायन के लिए संगीत शिक्षक श्री रमेश मिश्रा को भी सम्मानित किया गया.

जबलपुर । दिनांक 16/12/2022 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र हनुमान ताल जबलपुर द्वारा मंडला क्षेत्र के अंतर्गत बम्हनी बंजर में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया ।

जबलपुर। दिनांक 16.12.2022 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित चन्दवा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें सहकारी समिति के गठन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया।

मध्यप्रदेश की पहचान अब तकनीकी प्रधान राज्य के रूप में भी होगी : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी तक मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था। मध्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू होने के बाद अब प्रदेश की पहचान तकनीकी प्रधान राज्य के रूप में भी होगी। प्रदेश में इस नीति को तत्परता के साथ लागू किया जायेगा। नीति को तैयार करने में वैज्ञानिकों के अमूल्य योगदान की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशासन अकादमी भोपाल में मध्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2022 का विमोचन किया। उन्होंने नीति के उद्देश्यों एवं प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश भी डाला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस नीति के प्रमुख तीन उद्देश्य हैं। वैज्ञानिक सोच और समझ को दैनिक जीवन का अंग बनाना, सरकार और समाज में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना और नया सोचने, नया सीखने और नई पहल करने वाली पीढ़ी का निर्माण करना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विज्ञान का लोक व्यापीकरण किया जायेगा। इसके लिये सब मिल कर प्रयास करेंगे। जिज्ञासा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारी जिंदगी बदल देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है। विज्ञान और आध्यात्म एक-दूसरे के सहयोगी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में राज्य नवाचार कोष की स्थापना की जायेगी। भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने में विज्ञान और तकनीकी का पूरा उपयोग किया जायेगा। मध्यप्रदेश आध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। भारतीय कैलेण्डर अधिक सटीक और वैज्ञानिक है। मध्यप्रदेश का उज्जैन शहर प्राचीन काल-गणना का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम आज के युग में डाटा की महत्वता समझते हैं। कोडिंग लेब, क्यूरोसिटी लेब के लिए प्रयास करेंगे। भारतीय ज्ञान परम्परा का प्रभावी उपयोग करेंगे। हम आध्यात्म और विज्ञान में अग्रणी रहे हैं। वैद्य नाड़ी देख कर ही बीमारी का पता कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत की 5 ट्रिलियन की इकॉनोमी में मध्यप्रदेश 550 बिलियन का योगदान करेगा।

निवाड़ी। दिनांक 16/11/2022 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित (घूघसी) उरदौरा शाखा टेहरका जिला निवाड़ी में एक दिवसीय शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में समिति के कार्य प्रबंधन को विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में सहायक समिति प्रबंधक अरुण कुमार गोस्वामी, सहकारी प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय, विक्रेता संजीव अहिरवार, विक्रेता प्रदीप गोस्वामी, विक्रेता सुनील यादव,भृत्य धूराम नापित,भृत्य महेश रजक, चौकीदार जमुना अहिरवार, सहित समिति के कृषक सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे व कार्यक्रम संपन्न हुआ।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में कार्यशाला संपन्न

जबलपुर। सहकारिता में नवाचार को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं. ये विचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमरहाई जबलपुर की प्राचार्य श्रीमती मिथिलेश चौधरी ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा शाला में आयोजित सहकारी प्रशिक्षण की कार्यशाला में व्यक्त किये.

आयोजन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक और प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे ने नवाचार के अन्तर्गत महिलाओं की अधिकाधिक सहकारी समितियों के गठन पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं की सहकारी समितियों से महिलाओं में रोजगार के लिए जागरुकता बढ़ेगी.

इस अवसर पर श्री यशोवर्धन पाठक की सहकारी लेखों की पुस्तक सहकारी विचार दर्शन का विमोचन भी किया गया और उस पर चर्चा हुई. सभी को यह पुस्तक निशुल्क वितरित की गई.

सहकारी कार्यशाला का संचालन कंप्यूटर प्रशिक्षक श्री शोभित व्यौहार ने किया. स्वागत भाषण शाला शिक्षिका श्रीमती कीर्ति परौहा द्वारा किया गया. आभार प्रदर्शन श्री एन. पी . दुबे ने किया.

नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं

जनवरी 2023

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरू	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

फरवरी 2023

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	
गुरू	2	9	16	23	
शुक्र	3	10	17	24	
शनि	4	11	18	25	

मार्च 2023

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरू	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	31
शनि	4	11	18	25	

अप्रैल 2023

रवि	30	2	9	16	23
सोम		3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरू		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

मई 2023

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरू	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

जून 2023

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरू	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

जुलाई 2023

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरू		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

अगस्त 2023

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरू	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

सितम्बर 2023

रवि		3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरू		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

अक्टूबर 2023

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरू	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

नवम्बर 2023

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरू	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	
शनि	4	11	18	25	

दिसम्बर 2023

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरू		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

वर्ष 2023 की छुट्टियां

26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी संत रविदास जयन्ती, 18 फरवरी महाशिवरात्रि, 8 मार्च होली, 22 मार्च* गुड़ी पड़वा/महर्षि गौतम जयन्ती, 23 मार्च* चैती चांद, 30 मार्च रामनवमी, 4अप्रैल महावीर जयन्ती, 7अप्रैल पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), 14 अप्रैल* डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी, 22 अप्रैल परशुराम जयन्ती/ईद-उल-फित्र, 5 मई बुद्ध पूर्णिमा, 29 जून ईदुज्जुहा, 29 जुलाई मोहर्रम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 30अगस्त* रक्षाबंधन, 7 सितम्बर* जन्माष्टमी, 28 सितम्बर* मिलाद-उन-नबी, 2 अक्टूबर गाँधी जयन्ती, 24 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी), 28 अक्टूबर* महर्षि वाल्मीकी जयन्ती, 12 नवम्बर दीपावली, 15 नवम्बर* राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती), 27 नवम्बर गुरुनानक जयन्ती, 25 दिसम्बर ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस), *कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं.

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।